(b) and (c). An increase in the purchasing power of the Rupee is synonymous with a reduction in the price level and all Government policies are geared towards achieving that objective.

आयकर अधिकारियों द्वारा मारा गया छापा

3642. **श्री अम्बिका प्रसाद पांडेय :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक द्वेष भावना से आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों के बारे में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या बांदा जिले में अग्रवाल नर्सिंग होम के मालिक डा० चूड़ामणि अग्रवाल के यहां आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों के बारे में अप्रैल 1977 में दिये गये अभ्यावेदन पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने प्राधिकार के किये गये दुरुपयोग ज्यादतियों तथा अनैतिक चलनों की और ऐसे अन्य व्यक्तियों की जांच करेगा, जिन्होंने आपात स्थिति की घोषणा के लागू रहने की अवधि अथवा इससे तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के दौरान इस प्रकार के कार्य करने के लिये निदेश दिये हैं, अवप्रेरित किया हो अथवा उसमें अन्य किसी प्रकार का सहयोग दिया हो। यदि असंगत कारणों से कोई छापे मारे गये हों, तो वे उक्त आयोग की अधिकार सीमा के अंतर्गत आयेंगे।

(ख) जो परिसम्पतियां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश द्वारा रोक ली गयी हैं, उन को छोडकर शेष सभी परिसम्पतियां छोड दी गई हैं। उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध कर-निर्धारितों द्वारा किये गये आवेदन के सिलसिले में आयकर आयुक्त आगरा ने 25 जुलाई, 1977 को सुनवाई निश्चित की है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में जिला शाखा गिरिडीह में काम करने वाले डाक-कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3643. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 50 हजार या उस से अधिक आबादी वाले नगरों में कार्यरत अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देती है ;

(ख) यदि हां, तो जिला शाखा गिरिडीह (बिहार) में कार्यरत डाक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में उन कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की अदायगी के विद्यमान आदेशों के अधीन, नगरपालिका का दर्जा रखने